THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) and (b) In view of the total potential of about 17.00 MW in the country, the goal for generation of power from biomass materials has been revised to 350 MW for the Eighth Plan. A National Programme on Bagasse based Cogeneration and a Pilot Programme on Biomass combustion based power generation have been launched recently. Small scale biomass gasifiers are also being promoted for production of mechanical and electrical energy. A demonstration grid connected biomass gasifier project has also been taken up.

(c) Under the demonstration schemes of National Programme on Bagasse based Cogeneration and Pilot Programme on Biomass combustion, a maximum of 17 projects of minimum 5 MW capacity each are proposed to be taken up with financial assistance from Government during the Eigth Plan period. In addition, several more projects are likely to be taken up through investments by private sector.

(d) Installation costs generally vary from Rs. 2.50—Rs. 4.00 crore per megawatt. They are dependent upon the site, type of biomass proposed to be used and capacity of the project.

ज्वारीय विद्युत परियोजना

2682. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को ज्वारीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने तथा इसका विस्तार करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) सुन्दरवन (पश्चिम बंगाल) में दुर्गाद्विनी क्रीक नामक स्थान पर लगभग 2 मेवा क्षमता के प्रस्तावित ज्वारीय विद्युत संयंत्र पर संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव को नवम्बर, 1994 में मंजूरी दे दी गई है । इस परियोजना रिपोर्ट की लागत 8.00 लाख रुपये है जिसमें 50:50 के अनुपात में भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार की भागीदारी होगी ।

लघु पन-बिजली परियोजना की प्रगति

2683. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की लघु और अति लघु पन-बिजली परियोजनाओं पर हो रहे कार्य की गति अत्यन्त धीमी है ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित अवधि से पीछे चल रही परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) 3 मेवा स्टेशन क्षमता तक की लघु पन बिजली परियोजनाओं के लिए इस मंत्रालय की पूंजीगत आर्थिक राज सहायता योजना के अंतर्गत अनुमोदित की गई परियोजनाओं की राज्यों द्वारा कार्यान्वयन की प्रगति, विशेषकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में, कुछ धीमी देखी गई है ।

(ग) इस मंत्रालय ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के कार्य को तेज करने के लिए कई कदम उठाए हैं । इनमें परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था की स्थापना और पर्याप्त धनराशि का आवंटन किए जाने के लिए राज्यों को सलाह देना शामिल है । उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि उत्क्रमणों और सिविल तथा इलैक्ट्रिकल कार्यों के लिए आदेश जारी करने के कार्य में तेजी लायें । प्रगति की निरन्तर मानीटरिंग और समीक्षा की जा रही है ।